(च) यदि हां तो किन-किन देशों के साथ बातचीत की गई है और क्या इस बात-चीत संतोषजनक परिणाम निकले हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो भावी कार्यवाही की मोटे तौर पर रूप-रेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री : (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (छ) यह सही है कि भारतीय ठेकेदारों/निर्यातकों द्वारा इराक को परियोजना/उत्पाद निर्यातों की वजह से कुल 640 मिलियन अमरीकी डालर की राशि इराक पर बकाया है। इस राशि में से भारत-इराक आस्थगित भुगतान प्रबन्धों के तहत प्राप्त की जाने वाली राशि 485 मिलियन अमरीकी डालर है। भारत तथा इराक की सरकारों के बीच आस्थगित भुगतान प्रबन्धों के तहत इराक से तेल की खरीदारी के लिए तेल भुगतानों का कुछ अंश परियोजना निर्यातकों को देय राशि में समायोजित कर दिया गया है। खाड़ी संकट आरम्भ होने तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा व्यापार रोक लगाए जाने से कच्चे तेल का आयात नहीं किया जा सका था और इसलिए अगस्त 1990 से आस्थगित भुगतान प्रबन्ध के तहत कोई भुगतान वसूल नहीं किए गए। सरकार ने इस संभावना के संबंध में कि इराक जनवरी 1991 में भारतीय निर्माण कंपनियों को देय राशि के बदले भारत को तेल दे, इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् समिति के साथ उठाया है। परंतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् समिति की प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं रही है। अतः इराक से और आगे भुगतान लेने के प्रबन्ध इराक पर लगी संयुक्त राष्ट्र व्यापार रोक हटाए जाने के बाद ही किए जा सकेंगे।

Issue of Ration Cards to illegal migrants

*187. SHRI SATYA PRAKASH MALVIYA : SHRI SATISH PRADHAN :

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC] DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal to change the procedure for 1097 RSS/94—3. issuing rat on card to prevent illegal foreign nationals, especially Bangladeshi infiiltrators, who are getting ration cards very easily in the country, particularly in Delhi, Bihar and Assam, if so, the details thereof;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) the details of the measures taken| proposed to be taken to prevent illegal migrants from Bangladesh from getting ration cards ?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI A.K. ANTONY):

(a) to (c) The operational responsibility for implementing the Public Distribution System (PDS) in the country is with the State Governments and UT Administration. Decisions regarding the opening of fair price shops, eligibility criteria for issue of ration cards to the bona fide consumers and operational procedures and regulatory measures are taken by the State Governments/UT Administrations. Bona fide residents of a State are generally .issued ration cards for getting access to PDS. Ration card is not intended to be linked to any other benefit or confer any entitlement other than access to PDS.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निगरानी रखने में लोगों की भागीदारी

188. श्री छोटू भाई पटेल
श्री अजीत जोगी:

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निगरानी रखने में लोगों की, विशेषकर उपभोक्ताओं की, भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को क्या निदेश दिये गये हैं;

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह सच है कि इस प्रणाली को संचालित करने वाले अधिकांश सहकारी उपभोक्ता-भंडारों में वास्तविक उपभोक्ताओं की कोई भागीदारी नहीं है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए. के. एन्टनी):— (क) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की परिवीक्षा में उपभोक्ताओं की कारगर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी है कि वे राज्य, जिला, ब्लाक और उचित दर स्तर पर उपभोक्ताओं की सतर्कता/परामर्शदात्री समितियां गठित करें। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे इन समितियों में महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रमुख नागरिकों, राशन कार्ड धारियों और स्वैच्छिक संगठनों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दें। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले क्षेत्रों में सतर्कता/उचित दर दुकान स्तर की सतर्कता समितियां गठित करने पर विशेष बल दिया गया है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली ब्लाकों में अधिकांश उचित दर दुकानों के लिए ऐसी समितियां गठित कर ली गई हैं। उपभोक्ता भंडार चलाने वाली सहकारी समितियों का प्रबंधन आमतौर पर ऐसी संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जिनमें उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व रहता है।

Import of Natural Rubber

*189. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Wall the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to permit the import of natural rubber;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the quantity and value of rubber proposed to be imported ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) to (c) The estimated production and consumption of natural rubber during 1993-94 is 4,40,000 tonnes and 4,51,000 tonnes respectively. In order to meet the demand-supply gap, it has been decided to allow the rubber consuming industry to import 10,000 Metric Tonnes of natural rubber during the lean production period of 1993-94. The amount of foreign exchange involved in this import will depend on the price of natural rubber in the international market on the date of contract for purchase.

Curb on Import of Aromatic Plants

*190. PROF. SAURIN BHATTACHARYA : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to news item published in the 'Economic Times', New Delhi dated the 27th April, 1993 captioned "Curbs on import of aromatic plants hit herlwl medicines";

(b) whether Government have estimated the annual expenditure incurred by importers of herbs for the last three years with values of exports made by them or medicine manufacturers; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) to (c) Yes, Sir. Under the Export and Import Policy, 1992—97 (Revised Edition : March 1993), the "crude drugs re-quiied for making Ayurvedic and Unaui medicines" continue to be freely importable. However, Government have notified on 31-3-1993 a list of such "crude drugs" which can be imported, without a licence, by the manufacturers of such medicines subject to Actual User condition. The Actual User condition has